[Secretary]

Houses on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1965:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be extended up to the 30th November, 1968".

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

SEVENTH REPORT

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): Sir, I beg to present the Seventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.23 HRS.

CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters."

Shri George Fernandes wants to oppose it. Normally at the introduction stage it is not opposed.

श्री जार्ज फरनेंडीज (बम्बई दक्षिण): मैं नियमों के अनुसार ही इसका विरोध कर रहा हूं। ऐसा करने के खास कारण भी हैं। उन से विवश हो कर ही मुझे इसका इस स्टेज पर विरोध करना पड़ रहा है।

दो बातें इस बिल के द्वारा हमारे गृह मंत्री महोदय करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि क्लाज 2 के तहत वह इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 153 (ए) को एमेंड करना चाहते हैं और क्लाज 3 के द्वारा इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 505 को एमेंड करना चाहते हैं। आगे आप सैक्शन 6 को देखें। इस में माननीय मंत्री जी का जो सुझाव है वह बहुत ही खतरनाक है और इसी को ले कर मैं इस बिल का बुनियादी तौर पर विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस को सदन में पेश करने की अनुमति न दी जाए।

गृह मंत्री महोदय ने इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजंज में कहा है अभी हाल ही में नैशनल इंटेग्रेशन काउंसिल की बैठक श्रीनगर में हुई थी वहां पंजाब स्पेशल पावर्ज प्रेस एक्ट 1956 से सम्बन्धित जो भी कानून है उसको पूरे देश पर लागू करने के बारे में विचार हुआ था और उस विचार को कार्यान्वित करने के लिए ही वह इस सदन के सामने आ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले आंध्र में इसी किस्म का एक विधेयक आंध्र सरकार ने वहां की विधान सभा में पेश किया था जिस में अखबारों के ऊपर कई किस्म के निर्बन्ध लाने का प्रयास किया गया था। उस विधेयक को ले कर आंध्र की विधान सभा में सख्त विरोध प्रकट किया गया था। उस विधेयक पर इस सदन में भी काफी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान इनफर्मेशन मिनिस्टर ने यह बताया था कि आंध्र सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार की बातचीत चल रही है, उस विधेयक का क्या किया जाए, इसके बारे में उसके साथ बातचीत चल रही है। जब केन्द्रीय सरकार उस विधेयक के

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-8-68.

सम्बन्ध में आंध्र सरकार से बातचीत चला रही है और उस बिल का अंतिम स्वरूप क्या हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है तो मैं यह नहीं समझ सका हूं कि सदन में क्रिमिनल एंड इलैक्शन लाज एमेंडमेंट बिल के माध्यम से अखबारों के ऊपर बंधन लगाने वाले इस विधेयक को सरकार क्यों पेश करने जा रही है। इस में बहुत खतरनाक चीज़ है। क्लाज 6 को आप देखें। क्या कह रहे हैं इस में मंत्री महोदय :

"The Central Government or a State Government or any authority so authorised by the Central Government in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony and affecting or likely to affect public order, may, by order in writing addressed to the printer, publisher or editor, prohibit the printing or publication of any document or any class of documents of any matter relating to a particular subject or class of subjects for a specified period or in a particular issue or issues of a a newspaper or periodical;"

MR. SPEAKER: You need not go into the merits now. You will have another occasion to go into the merits of the Bill.

श्री जार्ज फरनेंडीज : सिर्फ एक जो खतरा है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय इसके द्वारा यह करना चाहते हैं कि अगर किसी खबर के छपने से पब्लिक आर्डर पर कुछ गलत असर पड़ने की आशंका हो या गलत असर पड़ रहा हो तो उस खबर को छपने से वह रोक सकेंगे और महीने तक उस खबर को छपने से रोके रखा जा सकेगा। यह अधिकार सरकार इस विधेयक द्वारा प्राप्त करना चाहती है। खुले तौर पर सैंसरशिप वाली बात आज हम लोगों के सामने आ रही है।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। 19 तारिख को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है। हो सकता है कि गृह-मंत्री महोदय का खयाल हो कि इस हड़ताल से पब्लिक आर्डर पर कुछ गलत असर पैदा होगा। इस वास्ते गृह मंत्री का यह विचार हो सकता है कि यह कानून पास हो जाए तो इसके अन्तर्गत वह इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चूंकि पब्लिक आर्डर पर हड़ताल होने से और उसकी खबरें छपने से गलत असर पड़ने का डर है, इसलिए हड़ताल के सम्बन्ध में कोई भी खबर को छपने से वह रोकने का प्रयास कर सकते हैं और इस कानून का ऐसा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं...

अध्यक्ष महोदय : मैरिट्स में आप न जाएं...

श्री जार्ज फरनेंडीज : मैं आखिरी जुमला कह कर समाप्त करता हूं। सैंसर करके खबरों को मंत्री महोदय इस कानून के माध्यम से देना चाहते हैं। इसका हम सख्त विरोध करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस विधेयक के बारे में आल इंडिया न्यूज-पेपर्ज एडीटर्ज कान्फ्रेंस के लोगों से, इंडियन फैड्रेशन आफ वर्किंग जरनलिस्ट्स के लोगों से और इस सदन के उन सदस्यों से जिन को सैंसरशिप के बारे में कुछ तजुर्बा हो, जिन की वाक-स्वतंत्रय में और अखबारों की स्वतंत्रता में कुछ आस्था हो, सलाह मश्विरा करने के बाद ही इस विधेयक को यहां पेश करें। इसलिए मैं इसका सख्त विरोध अभी से करना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं इस पर आपत्ति करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि यह विधेयक विवाद-ग्रस्त है और इस पर

[श्री जार्ज फरनेंडीज:]

बारीकी से चर्चा होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे समिति में भेजने का सुझाव ला रहे हैं?

SHRI Y. B. CHAVAN: I am in the hands of the House in this matter. I am not taking any particular line. But I thought that this Bill should be moved because, when it was discussed in the National Integration Council, the intention was to expedite this process. I did not want anyone to say that the Government was tardy in this matter. I want to see that the Bill becomes Act as soon as possible. If the House wants to take it to the Select Committee, I do not want to come in the way. I leave it to the judgement of the House. I think, the powers are urgently necessary.

SHRI RANGA (Srikakulam): I only want to ask him one question. When he tries to give an answer to the speech made by my hon. friend, Shri Fernandes, I would like him to tell us what he proposes to do in regard to the Andhra Bill. I know that in the other House he has admitted that, so far as he could see, it had gone far beyond the scope of the Resolution or the objective that they have stated in their Srinagar Conference. In view of the fact that this Bill seeks to make an all-India law giving permission or option to the State Governments to adopt it with or without modifications, would the hon. Minister tell us whether he is already in contact with the Andhra Government in order to see that they do not proceed with that Bill until this Bill becomes an Act and then they examine their Bill in the light of whatever Act we would be passing in this House.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पायंट आफ़ आर्डर है। नियम 65 में कहा गया है:

> "The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be one month unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice."

इस के साथ ही आप नियम 69 और 70 को भी देख लीजिए। किसी भी विधेयक को तभी पूरा माना जायेगा, जब उस को पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया गया हो...

MR. SPEAKER: You are talking about Private Members. The Home Minister is not a Private Member.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is a Public Member.

श्री मधु लिमये: लेकिन फ़िनांशल मेमोरेंडम और डेलीगेटिव लेजिसलेशन का मेमोरेंडम तो सभी बिलों के लिए ज़रूरी हैं। डेलीगेटिड लेजिसलेशन का मेमोरेंडम तो इस बिल के साथ दिया गया है।

MR. SPEAKER: A point was raised about referring it to the Select Committee. That was an important one. We could understand that...

श्री मधु लिमये: लेकिन जब यह बिल आ ही नहीं सकता है, तो उस के सिलेक्ट कमेटी में जाने का सवाल कहां है।

इस बिल के साथ जो फ़िनांशल मेमोरेंडम दिया गया है, वह अधूरा है। आज के बुलिटन नम्बर 2 में इस बारे में कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई है। इस लिए जो बिल हमारे सामने आया है, वह अधूरा है। मंत्री महोदय उस को पूर्ण बना कर कल इस सदन के सामने पेश करें।

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): I know, at this stage, when the Bill is being introduced, as a convention...

MR. SPEAKER: Not only convention; even if it is opposed, only one member can oppose. Rules are very strict and are very clear.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: But, Sir from a different point of view I want to say one thing. This Bill has been brought as a result of the discussions at the National Integration Conference held in Srinagar.

As you are probably aware, not even a single leader of the minority community was present there. Moreover, what will be done hereby the bill? There will be a serious interference in religious matters. It is said in Clause 2 sub-clause (2):

> "Whoever commits an offence specified in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which shall not be less than two years but which may extend to five years and shall also be liable to fine."

It is a very serious and dangerous provision which has to be considered seriously. Therefore, I support my hon. friend, Mr. Fernandes that the Bill should go to a Select Committee.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): I would like to know whether this is a matter relating to List II or not, because it relates to law and order. Therefore, I believe Article 249 of the Constitution is attracted. I would request the Hon. Minister to examine whether it would attract Article 249 or not requiring resolution by the Council of States enabling Parliament to legislate regarding List II matters. It is a serious matter because the very devil of communalism is being sought to be attacked and put an end to.

SHRI Y. B. CHAVAN: As far as the legal aspects are concerned, I have also consulted the legal advisers, and I am proceeding on the basis of the advice that I have received and the advice is that this Bill does not conflict with that Article.

Shri George Fernandes has raised the point whether though we are introducing this Bill, here, we have at the same time advised the State Government to deal with the same Act in some different ways. I would like to make the facts and the record clear in this matter.

The first thing is that the Andhra Bill, we are advised, is before the Select Committee there. I do not know whether I could advise the Chief Minister or the Chief Minister can act on it, because the Bill is in the hands of the State Legislature, and the State Legislature has its own powers, functions and sovereignty. I do not want to interfere with that.

But, certainly, I have said one thing in the other House that as far as the content of the Bill is concerned, the Bill goes beyond the recommendations of the National Integration Council. It is a fact, I do not think that even the Chief Minister of Andhra Pradesh would dispute this one particular fact. This Bill and the Andhra Bill are quite different Bills in their content as such.

This Bill takes only clause 2 of the Punjab Security Bill; it does not go beyond that. The Andhra Bill goes even beyond the Punjab Security Bill. It is quite a comprehensive Bill.

Therefore, I had only said that I would be willing to discuss this matter with the Chief Ministers. Beyond that I cannot give any assurance to this House.

As regards the point raised about 'public order', I would submit that it is not likely to be used for any public order purposes as such unconnected with communal hatred etc. The wording of the Bill is like that. I would read out the same thing which he had read earlier, and possibly my reading itself will make the position very clear. The wording is as follows:—

> "The Central Government or a State or any authority so authorised by the Central Government in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony and affecting or likely to affect public order...."

The wording is not 'or' but 'and'. It is 'and', and that makes all the difference. Anything that will lead to a public order matter as such is not likely to be

[Shri Y. B. Chavan]

covered by this; anything that is likely to affect communal harmony which will lead to a public order matter is likely to be covered.

No further explanations are necessary.

MR. SPEAKER: The question is: "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters."

The motion was adopted.

SHRI Y. B. CHAVAN: I introduce the Bill.

12.39 HRS.

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1968-69—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Uttar Pradesh Budget for the year 1968-69 as also the cut motions moved on the 26th August, 1968 in respect of those Demands.

As regards the discussion on U.P. Demands, I would like to say something. I know that a large number of Members would like to participate. But the time is very short. But immediately after this, we are having another discussion for about three hours regarding the extension of President's rule in U.P. I hope that the parties will see that those who have not participated on the Demands may be enabled to participate on that.

There is also one other suggestion namely that the Appropriation Bill may be passed and 4 hours may be taken in all on the resolution regarding the Proclamation in relation to U.P., so that everybody can speak in general on the problems of U.P., law and order etc., etc.

श्री मधु लिमये (मुंगेर): दो चर्चाओं को मिलाया न जाय। अलग अलग लिया जाय।

MR. SPEAKER: The Bill may be passed, and I was suggesting that 4 hours may be taken on the resolution. I thought that we could have one more hour on the discussion relating to U.P. Those who want to speak on this may speak on this. But I would appeal to those who have spoken already not to get up again.

SHRI RANGA (Srikakulam): What about the time for our party?

MR. SPEAKER: He will get twenty minutes, whether it be on this or the other one.

But we must finish these Supplementary Demands in one hour.

श्री विश्वनाथ पांडेय (सलेमपुर): श्रीमन्, कल मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन कितना ही सुन्दर और अच्छा हो लेकिन जन-प्रतिनिधि शासन के मुकाबिले लोग उस को पसंद नहीं करेंगे और यह दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में जन-प्रतिनिधि शासन नहीं है और जन-प्रतिनिधि शासन न होने की वजह से कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय राष्ट्रपति शासन के। इस सदन में काफी चर्चा किया गया है कि उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यह सही है। उस की जनसंख्या आज भारतवर्ष की जनसंख्या की 1/6 है। यह बात तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन 20 वर्षों के अन्तर्गत कोई विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन वह विकास नगण्य है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका है। उस का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं हुई है और न उस के पिछड़ेपन के आधार पर हुई है। दो पंच वर्षीय योजनाएं जो व्यतीत हुई उस में कोई भी केन्द्रीय उपक्रम